www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 250 | जौनपुर गुरूवार, 30 अप्रैल 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने डाला वोट

कोलकाता, (एजेंसी)। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में आज सात जिलों की 142 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और आम लोगों से लेकर मंत्री और सांसद भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच हिंदी सिनेमा के डिस्को डांसर और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती भी अपना वोट डालने पहुंचे और साफ किया कि इस बार बंगाल में बदलाव की बाढ़ आने वाली है।वोट देने के बाद अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने विश्वास दिलाया कि चुनाव पूरे निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मुझे यकीन है कि चुनाव बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। वोटिंग शेयर बढ़ने के सवाल पर अभिनेता ने कहा, ष्जो लोगों की भीड़ देख रहा हूं उससे साफ है कि पहले चरण का रिकॉर्ड भी टूटेगा और वोटिंग 90 फीसदी से भी आगे जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन होने वाला है, लेकिन जीत की घोषणा होने से पहले मैं कुछ ही कहूंगा क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है।ष्भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती भले ही इस बार चुनावी मैदान में नहीं हैं, लेकिन पार्टी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि फिलहाल वे चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। अभिनेता लगातार मंचों से टीएमसी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर बंगाल में दोबारा टीएमसी आ जाती है।

आरबीआई ने शहरी को–ऑपरेटिव बैंकों को मजबूत बनाने के लिए लॉन्च किया मिशन सक्षम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को शहरी को–ऑपरेटिव बैंकों यानी सहकारी बैंकिंग (यूसीबी) सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए शमिशन सक्षमश (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) की शुरुआत की है। यह पूरे देश में लागू होने वाला एक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य को–ऑपरेटिव बैंकों की कार्यक्षमता और प्रबंधन को बेहतर बनाना है। भारतीय समाचार केंद्रीय बैंक ने एक नोट में बताया कि आरबीआई द्वारा शुरू किए गए इस मिशन के तहत करीब 1.40 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बैंक के बोर्ड मेंबर्स, सीनियर मैनेजमेंट, रिस्क, कंप्लायंस और ऑडिट विभाग के प्रमुखों के साथ–साथ आईटी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफलाइन (इन–पर्सन) और ऑनलाइन (ई–लर्निंग) दोनों माध्यमों से आयोजित किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। शसक्षमश का मतलब हैकृकाबिल और सक्षम बनाना। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराए जाएं,।

एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी कम करने का माध्यम नहीं, बल्कि विकास के 'ग्रोथ कॉरिडोर' : सीएम योगी

हरदोई, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को विकास की आधारशिला बताते हुए कहा कि यह परियोजना न सिर्फ आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी कम करने का माध्यम नहीं, बल्कि विकास के 'ग्रोथ कॉरिडोर' हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला आज उनके ही करकमलों से लोकार्पित होकर 'विजन से हकीकत' में बदल गई है। उन्होंने कहा कि कोविड–19 जैसी वैश्विक चुनौती के बावजूद इस परियोजना को तय समयसीमा में पूरा करना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने हरदोई की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि भक्त प्रह्लाद और भगवान नरसिंह की आस्था से जुड़ी रही है, और ऐसे पावन अवसर पर प्रधानमंत्री का स्वागत प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'नए भारत' की परिकल्पना अब 'नए उत्तर प्रदेश' के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। एक्सप्रेसवे, हाईवे और ग्रामीण सड़कों के व्यापक नेटवर्क ने प्रदेश में कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया है, जिससे निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता, दंगों और माफिया राज के कारण विकास की कल्पना भी मुश्किल थी, लेकिन बीते वर्षों में 'डबल इंजन सरकार' के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में चार लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का नेटवर्क तैयार हुआ है। हर जिला मुख्यालय को चार लेन और ब्लॉक–तहसील स्तर तक दो लेन सड़कों से जोड़ने का कार्य तेजी से पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी कम करने का माध्यम नहीं, बल्कि विकास के 'ग्रोथ कॉरिडोर' हैं।

अमित शाह ने कहा–सोनार बांग्ला' के लिए रिकॉर्ड मतदान करें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुधवार को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग की बीच मतदाताओं से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि बंगाल को भय, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के शासन से मुक्त करने के लिए महिलाएं और युवा अधिक से अधिक मतदान करें। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बंगाल को भय, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के शासन से मुक्त करने के लिए दूसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं, विशेषकर माताओं, बहनों और युवाओं से अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।" उन्होंने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से अपील करते हुए आगे लिखा, "आपका एक वोट बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करने के साथ–साथ महिलाओं को सुरक्षा देने का माध्यम बनेगा। बंगाल के युवाओं के सपनों को सिर्फ एक ऐसी सरकार ही पूरा कर सकती है, जिसके पास विकास का विजन भी हो और घुसपैठियों को चुन–चुन कर बाहर करने की संकल्प शक्ति भी हो। 'सोनार बांग्ला' के लिए रिकॉर्ड मतदान करें।" इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील की। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "आज 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का दूसरा चरण है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि वे रिकॉर्ड संख्या में बाहर निकलें और हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत व सहभागी बनाएं। विशेष रूप से, यह अत्यंत आवश्यक है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में आगे आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।" एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, "देश के एक सजग नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है ।

बंगाल में बदलाव की लहर, जनता ने पीएम मोदी के विजन को चुना– चिराग पासवान

पटना, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। एनडीए के नेताओं ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आ रही है। 4 मई को इसकी जानकारी सभी को हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, इस बार मेरा मानना है कि लंबे समय बाद, बंगाल चुनावों के बाद सामने आ रहे रुझान साफ तौर पर यह संकेत देते हैं कि बंगाल की जनता ने सरकार बदलने के लिए वोट दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर आधारित सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बंगाल की जनता लंबे समय से पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व, हिंसा, भ्रष्टाचार तथा तानाशाही जैसे मुद्दों के कारण परेशान रही है। बंगाल की जनता को कष्ट झेलना पड़ा है और इसी के खिलाफ जनता ने इस बार वोट दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जिस तरह नेता प्रतिपक्ष दूसरे राज्यों में जाकर बिहार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें किसी के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारी एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पर एलजेपी (आर) के सांसद अरुण भारती ने कहा कि लोग जब मतदान करने जाएं तो उनके ध्यान देना चाहिए कि वो किसको वोट डाल रहे हैं।

पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

हरदोई, (संवाददाता)। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, 6–लेन (जिसे 8–लेन तक बढ़ाया जा सकता है) वाला, एक्सेस–नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई–स्पीड कॉरिडोर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे, एक्सेस–नियंत्रित ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। लगभग 36,230 करोड़ की कुल लागत से निर्मित, गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय में काफी कमी आने की उम्मीद हैय यह समय मौजूदा 10–12 घंटों से घटकर लगभग 6 घंटे रह जाएगा। जिसे लगभग 36,230 करोड़ रुपये की कुल लागत से बनाया गया है।पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया कैसे युद्ध, अशांति और अस्थिरता में फंसी हुई है। दुनिया के बड़े–बड़े देशों की हालत खराब है। लेकिन भारत विकास के रास्ते पर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत के दुश्मनों को यह पसंद नहीं आ रहा है। भीतर बैठे कुछ लोग सत्ता की भूख में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर भी हम न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि विकास के नए–नए कीर्तिमान भी गढ़ रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस–वे इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर नहीं उठ सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे। यूपी को सपा और उसके सहयोगियों से सावधान रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि सपा विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। बीते दिनों एक बार फिर देश ने कांग्रेस और सपा का नारी विरोधी चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी, अगर यह संशोधन पास हो जाता तो 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलता। बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर लखनऊ और दिल्ली पहुंचती।

भारत में 2024-25 में 357 मिलियन टन हुआ कृषि उत्पादन : मनोज सिन्हा

जम्मू, (एजेंसी)। शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार को आयोजित सतत एवं जलवायु अनुकूल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार एवं नीतिगत ढांचा विषय पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने हिस्सा लिया। भारतीय समाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों और अन्य हितधारकों से जलवायु अनुकूलता विकसित करने और सतत कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों को रूपांतरित करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। उपराज्यपाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस लड़ाई में अग्रणी है और 2024–25 में कृषि उत्पादन 357 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2023–24 की तुलना में 25 मिलियन टन अधिक है, जिसमें बागवानी का उत्पादन 362 मिलियन टन रहा, उच्च मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण भी शामिल है। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि अन्य देशों से आगे बढ़कर भारत ने राष्ट्रव्यापी मृदा परीक्षण शुरू किया और 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। किसानों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो गई। एक राष्ट्रीय मिशन के तहत उच्च उत्पादकता वाले बीजों के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया। 2013–14 से लेकर अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालों की खरीद में 7,350 फीसदी और तिलहन की खरीद में 1,500 फीसदी की वृद्धि हुई है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तीव्र होते जा रहे हैं और पिछले वर्ष विभिन्न राज्यों में भीषण मौसम की स्थिति देखी गई।उपराज्यपाल ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि हम छोटे–मोटे बदलावों से आगे बढ़कर साहसिक, विज्ञान आधारित और किसान–केंद्रित परिवर्तन को अपनाएं।

राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला यज्ञ : सीएम भजनलाल

जयपुर, (एजेंसी)। राजस्थान में 1 मई से जनगणना की शुरुआत होगी। पहले नागरिक स्व–गणना कर सकते हैं और उसके बाद 16 मई से मकानों की गणना की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शएक्सश पर प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश जारी किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में अहम जानकारी देते हुए लिखा, राज्य में 1 मई से जनगणना 2027 का शुभारंभ होने जा रहा है। 1 मई से 15 मई 2026 तक नागरिक स्व–गणना कर सकेंगे एवं 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मी घर–घर जाकर मकानों की गणना करेंगे। उन्होंने आगे लिखा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना कर्मी लंबी दूरी तय कर आपके द्वार आएंगे। राजस्थान की अतिथि सत्कार की परंपरा को निभाते हुए उन्हें सही जानकारी प्रदान करें। आज आपके की ओर से दी गई सही सूचना, कल के विकसित राजस्थान और विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। सीएम भजनलाल ने पोस्ट में जनगणना से संबंधित लिंक भी शेयर किया। वहीं, अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की जनगणना 2027 सिर्फ आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला यज्ञ है। ये वो आधार है, जिस पर शासन की परियोजनाएं, संसाधनों का वितरण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित होती है। राजस्थान राज्य में जनगणना के पहले चरण में मकानों की सूची बनाने का काम और मकान की गणना का कार्य 16 मई से 14 जून तक घर–घर जाकर किया जाएगा। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि 1 मई से नागरिकों को स्व–गणना का अवसर मिलेगा, जिससे हर नागरिक इस राष्ट्रीय दायित्व का सहभागी बन सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जनगणना के कार्य में सहयोग देना, जैसे भवनों और मकानों पर जनगणना क्रमांक अंकित करने देना और मकानों की गणना से संबंधित प्रश्नों के सत्य, पूर्ण और स्पष्ट उत्तर देना विधि द्वारा निर्धारित कार्य है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की नई याचिका पर अरविंद केजरीवाल को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ईडी के समन से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन की अवहेलना मामले में श्आपश प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को नोटस जारी किया।ईडी ने केजरीवाल पर पूछताछ के लिए जारी समन की अवहेलना का आरोप लगाते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दायर की थी। हालांकि, निचली अदालत ने केजरीवाल को बरी कर दिया था। अदालत ने माना था कि उपलब्ध सबूत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सुनाया था। इसी फैसले को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी का आरोप था कि केजरीवाल ने अलग–अलग तारीखों पर जारी पांच समन के बावजूद एजेंसी के सामने पेशी नहीं दी। एजेंसी का कहना था कि एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से समन की अवहेलना गलत उदाहरण पेश करती है, इसलिए इस मामले में कार्रवाई जरूरी है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल ने बेतुके बहाने बनाए और जान–बूझकर जांच में शामिल न होने के लिए आधार तैयार किए। वहीं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई मामले में भी बुधवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कुछ प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए ।

नीदरलैंड और फिनलैंड की यात्राओं के दौरान कृषि व उद्योग जगत से जुड़े अहम समझौते किए : भगवंत मान

चंडीगढ़, (एजेंसी)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को नीदरलैंड और फिनलैंड की अपनी यात्राओं का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार ने कृषि, उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में ठोस वैश्विक साझेदारियां हासिल की हैं, जिनसे किसानों, युवाओं और राज्य की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ होगा। भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य पंजाब को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करके नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस यात्रा के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के तहत, पंजाब में एक नई सेमीकंडक्टर अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिससे मोहाली एक प्रमुख श्आईटी हबश के रूप में विकसित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए, हमारे शिक्षक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जा रहे हैं, ताकि पंजाब के बच्चों को आधुनिक तकनीकों से लैस शिक्षा प्रदान की जा सके। साथ ही, नीदरलैंड के महान हॉकी खिलाड़ी सलाहकार के रूप में हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए, बागवानी और फसल विविधीकरण पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके लिए पीएयू के सहयोग से आधुनिक कृषि मॉडल अपनाए जाएंगे।पुष्पकृषि और नई तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। पंजाब सरकार राज्य के हर क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर नंबर वन बनाने और जनता की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जेआईसीए समर्थित 1,300 करोड़ रुपये के अनुदान, वैश्विक कंपनियों की प्रबल रुचि और क्यूकेनहोफ से फिनलैंड तक उन्नत कृषि–तकनीक सहयोग के चलते ये रणनीतिक गठबंधन फसल विविधीकरण को गति देंगे, निवेश आकर्षित करेंगे और पंजाब को नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा उच्च मूल्य वाली कृषि के वैश्विक केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित करेंगे।

संपादकीय

पर्यावरण संकट की चुनौती

इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल गंभीर प्रयास करने की जरूरत है, किन्तु जलवायु नियंत्रण समझौतों के विषय में बहुत से देश विमुखता दिखा रहे हैं। जो मान भी रहे हैं, वे भी श्हरित प्रभाव गैसोंश के उत्सर्जन में कटौती के लिए स्व–घोषित लक्ष्य ही मानने तक सीमित रहना चाहते हैं। इस स्थिति से बाहर निकल कर कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। पिछली डेढ़ शताब्दी से, जब से औद्योगिक क्रांति ने विकास की गति तेज की और प्रकृति को जीतने की होड़ मच गई, मशीनों ने बंधक– निर्माण – शक्ति मानव के हाथ में दे दी, तब से विकास की परिभाषा भी धीरे–धीरे बदल गई। गुणात्मक जीवन के बजाय बाहुल्य को विकास माना जाने लगा। प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार का एक अंतहीन सिलसिला आरंभ हो गया। प्रकृति के दोहन से ही बाहुल्य के लिए सामान बनाए जा सकते थे, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के असीमित दोहन की शुरुआत हो गई। उपनिवेशवाद के दौर में कम मशीनी शक्ति वाले देशों पर तथाकथित विकसित देशों द्वारा कब्जे किये गए और उनके संसाधनों को बेदर्दी से नष्ट किया गया।सभ्य कहलाने वाले देशों द्वारा कमजोर देशों के मूल निवासियों को किस तरह प्रताड़ित किया, उनकी सभ्यताओं को असभ्य घोषित करके नष्ट करने का कार्य किया, वह अपने आप में घिनौना इतिहास है। इसके अवशेष अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में देखे जा सकते हैं, किन्तु यह आधुनिक सभ्यता अब अपने ही भार से भस्मासुर की तरह नष्ट होने की दिशा में बढ़ती प्रतीत हो रही है। इस सभ्यता ने अपने ही मूल पर आघात करना शुरू कर दिया है। हालांकि वैज्ञानिक समझ के विकास के चलते सब गलत दिशा को समझ भी रहे हैं, किन्तु विज्ञान का दुरूपयोग प्रकृति विनाशक शक्ति के रूप में किया जा रहा है। दुनिया के सबसे विद्वान वैज्ञानिकों को युद्ध–विज्ञान के विकास में संलग्न कर दिया गया है। निर्णय लेने वाले लोग तो आदिम क्रूर मानसिकता के ही वाहक बने हुए हैं जिनके हाथ में मशीन और विज्ञान, प्रकृति एवं प्राणी समाज के साथ मनमानी करने का हथियार बन गया है। ज्ञान, सुख और शांति का वाहक बनने के बजाय युद्ध और क्रूरता का वाहक बन गया है। इस स्थिति में श्संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमश के सातवें अधिवेशन में नैरोबी में प्रस्तुत की गई श्ग्लोबल आउटलुक 2025श रिपोर्ट पर्यावरण के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार को उजागर करती है और अपने तौर–तरीकों पर मानव समाज को पुनर्विचार करके संशोधित करने की दिशा दिखलाती है।जलवायु परिवर्तन प्रकृति के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार की प्रतिक्रिया के रूप में एक बड़े खतरे की चुनौती पेश कर रहा है। मशीनीकरण को चलाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की बड़े पैमाने पर जरूरत है वह जीवाश्म ईंधन से पैदा की जा रही है। इस उत्पादन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धुआं और जहरीली गैसें उत्सर्जित होती हैं जो श्हरित प्रभावश पैदा करके वायुमंडल के तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि कर रही हैं। तापमान वृद्धि से पूरे जलवायु का संतुलन हिल गया है। कहीं अतिवृष्टि हो रही है तो कहीं अनावृष्टि हो रही है। ग्लेशियर पिघल कर समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं जो आसन्न जल–संकट का कारण बनेंगे।रिपोर्ट के अनुसार श्हरित प्रभाव गैसोंश के उत्सर्जन से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान 2024 में बढ़कर 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। इस गति से वृद्धि होने पर जलवायु पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है जो आगे बढ़ता ही जाएगा। यदि तापमान वृद्धि को रोका नहीं गया तो इसके कारण जैव–विविधता पर भी बुरा असर पड़ने वाला है, जिससे 10 लाख प्रजातियों के लुप्त हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। 20 से 40 प्रतिशत भूभाग वैश्विक स्तर पर अनुपजाऊ होने के कगार पर है

ब्रिटिशकालीन विरासत के नाम बदलने का सवाल

भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है। ऐसे में सिविल लाइंस जैसे नामों–प्रतीकों को बदलना या हटाना सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि मानसिकता को डीकॉलोनाइज करने की दिशा में अहम कदम है। हालांकि इतिहास भुलाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे संग्रहालयों व उचित संरक्षण के जरिये याद रखा जाए। दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और कई अन्य शहरों में सिविल लाइंस की चौड़ी सड़कें, दोनों तरफ खड़े विशाल और बुजुर्ग पेड़, पुराने गिरजाघर और औपनिवेशिक इमारतें ब्रिटिश राज के विलासी जीवन की याद दिलाते हैं। अब भारत सरकार इन सिविल लाइंस क्षेत्रों से ब्रिटिश काल के प्रतीकों को हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह कदम वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से डीकॉलोनाइज्ड बनाने के विजन का हिस्सा है। ये इलाके विशेष रूप से ब्रिटिश सिविलियन अधिकारियों जैसे डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदि के लिए बनाए गए थे, ताकि वे भारतीय 'नेटिव टाउन' से अलग, आरामदेह जीवन व्यतीत कर सकें। 19वीं शताब्दी में विकसित ये 'व्हाइट टाउन' आज भी अनेक शहरों में मौजूद हैं। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिशों ने अपनी सुरक्षा और श्रेष्ठता को और मजबूत करने के लिए शहरों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ओर पुरानी, भीड़भाड़ वाली भारतीय बस्तियां, तो दूसरी ओर विस्तृत सड़कें, हरे–भरे बगीचे, बड़े बंगले और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 'सिविल लाइंस'। ये क्षेत्र कैंटोनमेंट से अलग लेकिन निकट थे। यहां ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स, जज, कलेक्टर आदि उच्च अधिकारी रहते थे। दिल्ली में सिविल लाइंस का इतिहास 1857 से गहराई से जुड़ा है। मुगल राजधानी शाहजहानाबाद (पुरानी दिल्ली) के उत्तर में, यमुना नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र ब्रिटिशों का पहला प्रमुख आवासीय केंद्र बना। 1803 में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वे शुरू में कश्मीरी गेट क्षेत्र में रहते थे, लेकिन 1857 के विद्रोह ने सब बदल दिया। विद्रोहियों ने ब्रिटिश बंगलों को आग के हवाले कर दिया। विद्रोह दबाने के बाद अंग्रेजों ने सिविल लाइंस को रणनीतिक रूप से और मजबूत किया। यह क्षेत्र रिज (उत्तर दिल्ली रिज) के पास स्थित था, जो सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। लुटियंस दिल्ली (नई दिल्ली) बनने तक सिविल लाइंस ही ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य केंद्र रहा। आज भी यहां निकोलसन कब्रिस्तान मौजूद है, जो 1857 में स्थापित हुआ। यह कब्रिस्तान ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की मौत के बाद बनाया गया था। यहां ब्रिगेडियर जॉन निकोलसन की कब्र है, जो विद्रोह दबाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे। इस कब्रिस्तान के पास बना चर्च स्थानीय ईसाई समुदाय के लिए था। यह पूरा इलाका आज भी रहस्यमयी कहानियों और पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़ा माना जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतीक है कुदसिया बाग। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला की बेगम कुदसिया द्वारा 1748 में बनाया गया यह चारबाग शैली का सुंदर बगीचा 1857 में ब्रिटिशों द्वारा नष्ट कर दिया गया। बाद में यहां अंग्रेजी शैली का बंगला बनाया गया। हाथी गेट भी यहीं है, जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मोटी दीवारों वाला यह गेट ब्रिटिश काल में सिविल लाइंस की सीमा बन गया। मैडंस होटल (अब ओबेरॉय मैडंस) दिल्ली के सिविल लाइंस का एक शानदार नमूना है। यह हेरिटेज होटल सफेद इमारत, पुरानी लॉबी और स्विमिंग पूल के साथ औपनिवेशिक वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है।

लोक के प्रति कब जवाबदेह बनेगी नौकरशाही

उमेश

सरदार पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को 'स्टील फ्रेम' बताया था। संविधान सभा में प्रशासनिक सेवा पर बहस के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए मजबूत और तटस्थ नौकरशाही पर जोर दिया था। हालांकि अंग्रेजों के नौकरशाह रह चुके एचवी कामथ को चिंता थी कि वैधानिक सुरक्षा नौकरशाही को गैरजवाबदेह और असल 'शासक' बना सकती है। एक अप्रैल को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के मालदा की घटना में नौकरशाही ने जैसा रूख अख्तियार किया है, उसे देख लगता है कि पटेल के भरोसे की तुलना में एचवी कामथ की चिंता समय की शिला पर सटीक साबित हुई है। मालदा में पूरे नौ घंटे तक सात न्यायिक अधिकारियों को सियासी कार्यकर्ता के मुखौटे वाले अपराधियों ने बंधक बनाए रखा। उस दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी मुख्य सचिव से संपर्क करने में नाकाम रहे। दिलचस्प यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब–तलब किया तो उन्होंने माफी मांग कर काम चला लिया। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शीर्ष अधिकारियों को सबक सिखाने से पीछे नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह माफी से ही संतुष्ट हो गया। देश को अपने लोकतंत्र पर गर्व है, लेकिन इस व्यवस्था में राजनीतिक तंत्र के साथ ही प्रशासनिक और पुलिस अफसर लगातार मजबूत हुए हैं। अंग्रेज सरकार ने इंडियन सिविल सेवा यानी आईसीएस का गठन अपने राजकाज को मजबूत करने के लिए किया था। इसलिए शुरूआती दौर में इसमें गोरे लोगों को ही तवज्जो मिली। अंग्रेज सरकार भारतीयों को गुलाम मानती थी, लिहाजा उसके अफसर भी भारतीयों से उसी अंदाज में पेश आते थे। आजादी के बाद नौकरशाही के इस चरित्र को बदलने की कोशिश के तहत तटस्थ ब्यूरोक्रेसी के रूप में आईएएस कैडर बनाया गया। गांधी मानते थे कि आधुनिक राज व्यवस्था और नौकरशाही में हिंसा का वर्चस्व है। गांधी जी श्ट्रस्टीशिपश के सिद्धांत के अनुसार प्रशासनिक या आर्थिक रूप से ताकतवर लोगों से उम्मीद करते थे कि वे संसाधनों के स्वामी नहीं, बल्कि रक्षक की तरह व्यवहार करें। इसी अंदाज में नौकरशाही को सेवक बनाने की कोशिश हुई। लेकिन क्या नौकराशाह सेवक बन पाए? वे सिर्फ उन राजनीतिक आकाओं के ही सेवक बन पाए हैं, जो ताकतवर हैं और जिनसे उन्हें भविष्य में मलाईदार पदों और ताकत की उम्मीद है। यही वजह है कि आजादी के 79 साल बाद भी नौकरशाही का ज्यादातर हिस्सा सामंती मानसिकता से ही प्रभावित नजर आता है। जनता को वह अपनी रियाया मानता है। लोक से सामंतों जैसा व्यवहार करने में ही उसे हेठी नजर आती है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला का कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का फोन नहीं उठाना इसी सोच का प्रतीक है। यह उस आशंका का भी जीवंत उदाहरण है, जो एचवी कामथ को परेशान कर रही थी। दिलचस्प यह है कि दुष्यंत नरियाला को 16 मार्च को ही चुनाव आयोग ने नंदिनी चक्रवर्ती की जगह नया मुख्य सचिव बनाया था, ताकि वे निष्पक्ष चुनाव करा सकें। नरियाला के व्यवहार से साफ है कि न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में उनका रवैया तटस्थ नौकरशाह की बजाय राज्य की मौजूदा सत्ता के इशारे पर ही काम करने वाले जैसा रहा। लोकतंत्र, लोक यानी आम लोगों का तंत्र है। लेकिन हकीकत में यह राजनीतिक दलों का तंत्र है और इस तंत्र में लोक की भूमिका महज वोट देने तक ही सीमित है। इस तंत्र में नौकरशाही की जवाबदेही राजनीति के हर अच्छे–बुरे कामों में साथ देने और कई बार उसका कहार बनने तक सीमित रह गई है। सरदार पटेल जब इस तंत्र को स्टील फ्रेम कह रहे थे, तो उनका आशय यह था कि भावी नौकरशाही आम लोगों की भलाई और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। पटेल को उम्मीद रही होगी कि नौकरशाह लोक के प्रति जब जवाबदेह होंगे, तब ऐश्वर्य पर उनकी निगाह कम होगी। लेकिन इसके

ठीक उलट हो रहा है। नौकरशाही के बड़े हिस्से को अपनी मूल भूमिका की चिंता नहीं सताती। उसकी पूरी कोशिश खुद और खुद के कैडर को मजूबत करने और ज्यादा सुविधाएं जुटाने पर केंद्रित रहती है। ज्यादातर नौकरशाहों के लिए आमजन ठीक वैसी ही प्रजा हैं, जिस तरह अंग्रेजों के थे। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव का व्यवहार इसी सोच का उदाहरण है। जब कोई आईएएस किसी फरियादी की बात सुनने के लिए जमीन पर बैठ जाता है, या ऐसा ही सामान्य कदम उठाता है तो वह घटना खबर बन जाती है। इसकी वजह यही है कि अफसरों से ऐसे व्यवहार की उम्मीद ही नहीं होती। जनमानस की सोच ऐसी है तो यह मान लेना चाहिए कि पटेल की सोच के मुताबिक नौकरशाही विकसित नहीं हुई, बल्कि एचवी कामथ जैसे लोगों की आशंका ही सही साबित हुई है। नौकरशाही में जब भी किसी का चयन होता है, उसके पड़ोसी और रिश्तेदार तक मान लेते हैं कि कुछ ही दिनों में उसकी कई पुश्तों का इंतजाम हो जाएगा। ज्यादातर ऐसा होता भी है। मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने लोकपाल की व्यवस्था कर रखी है। वहां आए दिन जिस तरह अधिकारियों के घरों से नोटों की गड्डियां निकलती हैं, उनकी संपत्ति के ब्यौरे सामने आते हैं, उससे पता चलता है कि अफसर बनना जमींदारी हासिल करने से भी ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे अफसरों पर कड़ी कार्रवाइयां नजीर बननी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। अफसरशाही का बड़ा हिस्सा अब भी तंत्र के दोहन की प्रक्रिया में शिद्दत से शामिल है। हाल ही में बिहार के एक सब डिविजनल पुलिस अफसर के बारे में समाचार आया कि उनकी नौकरानी भी थार से चलती है। ऐसा नहीं कि नौकरशाही में ईमानदार लोग नहीं हैं। अशोक खेमका और संजीव चतुर्वेदी इसके उदाहरण हैं। लेकिन उन्हें ना तो नौकरशाही चौन से बैठने देती है और ना ही राजनीतिक आका। नौकरशाही को तटस्थ और ईमानदार बनाए रखने के लिए पचासों कमेटियां बन चुकी हैं, दो प्रशासनिक सुधार आयोग बन चुके हैं। पहले आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे तो दूसरे के कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली। जान लेना चाहिए कि स्वाधीनता संग्राम में कूदने से पहले मोरार जी भी सिविल सेवा के अधिकारी थे। दोनों आयोगों ने कई सुझाव दिए, कुछ लागू भी हुए। लेकिन असल में नौकरशाही का चरित्र नहीं बदल पाया। वह लोकतांत्रिक नहीं हो पाई। आपातकाल के दिनों में जयप्रकाश नारायण ने नौकरशाही और पुलिस अफसरों से अपील की थी कि सरकार के असंवैधानिक आदेशों को वे न मानें। तब जेपी को अराजकतावादी कहा गया। हालांकि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि नौकरशाही के लिए राजनीति की बात टालना संभव नहीं हैं। एच वी अयंगार जैसे कुछ ही नौकरशाह होते हैं, जो सही बात कह सकते हैं और अपने राजनीतिक आका से अलग राय रख सकते हैं। राज्यों के गठन के पीछे भाषा को आधार बनाने के तत्कालीन गृह सचिव अयंगार विरोधी थे और उन्होंने अपने मंत्री सरदार पटेल के सामने उसे खुलकर रखा भी था। वैसे आज की राजनीति में पटेल जैसा हृदय रखने वाले लोग भी कम हैं।

केजरीवाल की विचारहीन राजनीति का यही अंजाम होना था

अनिल

ाजनीति समाचार राजनीति को हिकारत से देखने वाले केजरीवाल इस पार्टी के माध्यम से राजनीति में आए और छा भी गए। तब केजरीवाल, उनके साथियों, प्रशंसकों और मीडिया के भी एक बड़े हिस्से ने आम आदमी पार्टी के उदय को एक श्नई राजनीतिश के रूप में पेश किया था। हालांकि आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास से और राजनीति को पर्दे के पीछे से संचालित करने वाली ताकतों से परिचित लोग तब भी इस श्नयेपनश की हकीकत से बाखूबी वाकिफ्फ थे। निहित स्वार्थों से प्रेरित कॉरपोरेट नियंत्रित मीडिया के भरपूर समर्थन से परवान चढ़े एक विचारहीन और अराजक आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी का यही हश्र होना था, जो अभी हो रहा है। यह सही है कि आम आदमी पार्टी के विभाजन यानी राज्यसभा में उसके 10 में से 7 सांसदों को तोड़कर अपने पाले में लाने के काम को भाजपा ने अपने कु ख्यात श्ऑपेशन लोटसश के जरिये अंजाम दिया है, जिसमें हमेशा की तरह उसने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग का भी इस्तेमाल किया है। मगर आम आदमी पार्टी की इस स्थिति के लिए मूलतरू उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने राज्यसभा के लिए अपने जैसे ही विचारहीन और सिद्धांतहीन लोगों का चयन किया था। इस सिलसिले में उन पर राज्यसभा के टिकट बेचने और अपने सजातीय लोगों को उपकृत करने के आरोप भी लगे।दरअसल डेढ़ दशक पहले 2011 में जब तथाकथित गांधीवादी अण्णा हजारे को भ्रष्टाचार के विरोध का श्प्रतीक पुरुषश बना कर दिल्ली के जंतर–मंतर पर आंदोलन किया जा रहा था, तब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उस आंदोलन की तुलना अरब स्प्रिंग और काहिरा (मिस्र) के तहरीर चौक पर हुई क्रांति से कर रहा था। कॉरपोरेट घरानों से पोषित टेलीविजन चौनलों पर उस आंदोलन का 24 घंटे सीधा प्रसारण हो रहा था। अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन के मंच से राजनीतिक दलों और नेताओं को चोर, बेईमान और भ्रष्ट करार देते हुए राजनीति से अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे। उनके तेवरों को देखते हुए कोई नहीं कह सकता था कि जिस राजनीति को यह व्यक्ति पानी पी–पीकर कोस रहा है, कुछ ही महीनों बाद यही व्यक्ति उसी राजनीति का एक महत्वपूर्ण किरदार बन जाएगा। टीवी चौनलों में कार्यरत कुछ पत्रकार तो केजरीवाल में श्दूसरा चे ग्वाराश और अण्णा हजारे में श्दूसरा गांधीश तक देखने लगे थे।मगर चंद महीनों बाद ही अण्णा हजारे से अलग होकर केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। आंदोलन की कोख से जन्मी उनकी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ शहरी मध्य वर्ग के गुस्से का प्रतिनिधित्व करती हुई एक विद्रोही पार्टी माना गया, जिसका गर्भधारण सड़कों पर विरोध–प्रदर्शनों से हुआ था। राजनीति को हिकारत से देखने वाले केजरीवाल इस पार्टी के माध्यम से राजनीति में आए और छा भी गए। तब केजरीवाल, उनके साथियों, प्रशंसकों और मीडिया के भी एक बड़े हिस्से ने आम आदमी पार्टी के उदय को एक श्नई राजनीतिश के रूप में पेश किया था। हालांकि आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास से और राजनीति को पर्दे के पीछे से संचालित करने वाली ताकतों से परिचित लोग तब भी इस श्नयेपनश की हकीकत से बाखूबी वाकिफ्फ थे।अण्णा–केजरीवाल के आंदोलन को काफी कुछ बौद्धिक ऊर्जा उस विवेकानंद फाउंडेशन से मिली थी, जो व्यावहारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का थिंक टैंक है। उस आंदोलन के लिए सभी जरूरी साधन–संसाधन जुटाने में भी संघ का परोक्ष सहयोग था। आंदोलन के दौरान भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ केजरीवाल और उनके साथियों की बैठकें भी होती थीं। हालांकि आम लोगों के सामने भी इस श्नयेपन की राजनीतिश को उजागर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, जब 2014 आते–आते उस आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख चेहरे भाजपा से जुड़ते गए और केंद्र में उसकी सरकार बनने पर ऊंचे–ऊंचे पदों को प्राप्त हो गए। अण्णा–केजरीवाल का भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन और आम आदमी पार्टी के उदय की परिघटना इस लिहाज से भी गौरतलब थी कि अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों की मदद से फल–फूल रहे गैर सरकारी संगठनों व एनजीओ ने जन–आंदोलनों की धार कुंद करते हुए आक्रामक तेवर के साथ राजसत्ता तक अपनी पकड़ मजबूत करने की मुहिम तेज कर दी थी। देशी–विदेशी कॉरपोरेट घरानों की हमदर्द इन एजेंसियों के सिपहसालार आम जनता की बदहाली और बेसब्री का फायदा उठाते हुए उसे यह समझाने में जुट गए कि भ्रष्टाचार, गरीबी और महंगाई जैसी दुश्वारियों से निजात पाने के लिए किसी विचार की जरूरत नहीं है। ऐसा समझाने वालों में खुद अरविंद केजरीवाल भी थे। फिर भी यह सच है कि इतना सब कुछ उजागर होने के बावजूद केजरीवाल दस साल मुख्यमंत्री भी रह लिए। इस दौरान एक विरोधाभासी नारा भी लगा– श्मोदी फॉर पीएम–केजरीवाल फॉर सीएम।श इस नारे के अनुरूप केंद्र में मोदी की सरकार बनी और दिल्ली में केजरीवाल की। यह हैरानी की बात है कि एक ही मतदाता ने एक ही समय में दो अलग–अलग तरह की धाराओं में तैरने वालों को एक साथ कैसे चुन लिया? जाहिर है कि दोनों किरदारों के बीच दिखने वाला फर्क आभासी ही था। राजनीति राजनीति को संभावनाओं का खेल माना जाता है तो केजरीवाल संभावनाओं की पैदाइश है। उनके पास अपनी राजनीति का कोई मौलिक विचार नहीं है। उन्होंने अपने को भाजपा से भी बड़ा हिंदुत्ववादी दिखाने के लिए कई हास्यास्पद उपक्रम किए। देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए करेंसी नोटों पर लक्ष्मी–गणेश की तस्वीरें छापने जैसी मूर्खतापूर्ण मांग भी उन्होंने की। अपने को हनुमान भक्त बताया और लोगों को सरकारी खर्च पर अयोध्या सहित तमाम तीर्थस्थलों की यात्राएं भी कराईं। कोरोना महामारी के दौरान भाजपा की तर्ज पर तब्लीगी जमात के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने में भी उनकी सरकार ने कोई कोताही नहीं की और दिल्ली में दंगों के दौरान भी उनकी सरकार व पार्टी पीड़ितों के साथ न खड़ी होकर पुलिस के साथ और प्रकारांतर से केंद्र सरकार व भाजपा के साथ खड़ी दिखी। अनुच्छेद 370, राम मंदिर, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, नागरिकता कानून जैसे मुद्दों पर भी केजरीवाल भाजपा के साथ रहे। फिर जब उन्हें सुविधाजनक लगा तो वह कांग्रेस के साथ चले गए।।

चुनावी हिंसा रोकने में नाकाम आयोग

प. बंगाल

चुनाव के दूसरे और आखिरी दौर के मतदान से पहले भाजपा और चुनाव आयोग पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल दूसरे चरण से पहले चुनाव आयोग ने उत्तरप्रदेश के आईपीएस अधिकारी और काउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का नया पुलिस निरीक्षक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के फौरन बाद अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में वे फाल्टा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर के घर के पास खड़े हुए हैं और कहते हैं श्जहांगीर के घर वाले खड़े हैं, उसको बता देना कि कायदे से रहे... यह बार–बार जो खबर आ रही है कि जहांगीर के लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना और पछताना मत... ।श्अजय पाल शर्मा की इस भाषा और धमकी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, कुछ पूर्व पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चुनाव निरीक्षक का काम चुनाव आयोग की आंख और कान की तरह काम करना है, लेकिन उसमें मुंह बंद रखना होता है। यानी ऐसे सरेआम किसी का नाम लेकर धमकाना सही नहीं है। अजय पाल शर्मा की नियुक्ति पर एक तरफ टीएमसी ने सवाल उठाए, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें संभल और रामपुर में भाजपा का परखा हुआ एजेंट कहकर बता दिया है कि इस नियुक्ति के पीछे राजनैतिक दबाव काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग को इस पर फौरन सफाई देनी चाहिए। क्योंकि लगातार प.बंगाल में आयोग की कामकाज की शैली पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे चुनाव आयोग ने सोमवार, 27 अप्रैल को ही श्उपद्रवियोंश की एक नई सूची जारी की थी, जिसमें दूसरे दौर की 142 विधानसभा सीटों में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हजारों लोगों के नाम शामिल हैं। इन सभी सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। चुनाव आयोग द्वारा जारी इस सूची को एहतियाती कार्रवाई या हिरासत में लेने के अनुरोध के साथ जारी किया गया है। इसी तरह इस बार के चुनाव को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए चुनाव आयोग ने केन्द्रीय बलों की 2400 कंपनियां यानी करीब 2.4 लाख जवानों को तैनात किया है, जबकि लोकसभा चुनाव के लिए सभी 543 सीटों पर 3400 कंपनियां तैनात की गईं थी। इसके बावजूद राज्य में हिंसा की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सोमवार को टीएमसी की महिला और अनुसूचित जाति से आने वाली सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ। पत्थर बरसा कर उनकी कांच के शीशे तोड़े गए, जिसमें वो और उनका ड्राइवर दोनों घायल हुए हैं। टीएमसी का आरोप है कि हमला भाजपा के लोगों ने करवाया। एक पोस्ट में टीएमसी ने लिखा भी कि अमित शाह ने कहा था कि टीएमसी के लोगों को उल्टा लटका देंगे और अब ये हमला हुआ है। टीएमसी का ये भी आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर तैनात जवान और पुलिस निरीक्षक आधी रात को छापे मार रहे हैं, रात के सन्नाटे में आम नागरिकों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों में जबरदस्ती घुस रहे हैंय वे परिवारों को आतंकित कर रहे हैं, मतदाताओं को डरा–धमका रहे हैं।वहीं मिताली बाग पर हुए हमले के बाद सागरिका घोष ने सवाल उठाया है कि क्या यही भाजपा की नारी शक्ति के सम्मान की हकीकत है। हालांकि ऐसा ही हमला गोगहाट में भाजपा प्रत्याशी प्रशांत दिगार की गाड़ी पर भी किए जाने का आरोप लगा है। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। भाजपा ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है। इससे तीन दिन पहले एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई। इन हालात में सवाल ये है कि चुनाव आयोग के दावों का क्या हुआ। याद रहे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया था कि इस बार चुनाव में न श्छप्पाश यानी फर्जी वोटिंग होगी और न ही श्बूथ जैमिंगश यानी बूथ पर कब्जा होने दिया जाएगा। आयोग का कहना है

कि निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की असली पहचान है और 2021 जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी हाल में नहीं होने दी जाएगी। इस बार चुनाव आयोग की रणनीति पूरी तरह बदली हुई है। अब फोकस घटना होने के बाद कार्रवाई करने पर नहीं, बल्कि पहले से रोकथाम करने पर है। इसके लिए सुरक्षा बलों की पहले से तैनाती, संवेदनशील इलाकों की पहचान और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आयोग का साफ संदेश है कि चुनावी प्रक्रिया में डर, हिंसा और दबाव के लिए कोई जगह नहीं होगी। याद रहे कि चुनाव की घोषणा होते ही प. बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए थे। लेकिन इतनी कवायद का क्या मतलब अगर सांसद या प्रत्याशी या किसी कार्यकर्ता पर हमले की घटनाएं रुके ही नहीं। पहले दौर के मतदान के दिन किस तरह सुवेंदु सरकार को दौड़ा–दौड़ाकर पीटा गया था, वो नजारा भी जनता ने देखा है। इन तमाम घटनाओं से साफ है कि प.बंगाल में इस बार भी बिना हिंसा के चुनाव कराने में चुनाव आयोग नाकाम रहा है। अब उसके लिए चाहे किसी भी दल पर दोष डालें उससे आयोग अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता।

गुजरात ने विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत बनाए रखा : कुलपति प्रो. वंदना सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राज्यपाल सचिवालय के दिशा–निर्देशों के क्रम में गुजरात स्थापना दिवस के पूर्व दिवस पर विविध कार्यक्रमों को उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रो. वंदना सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा से हुआ। इसके साथ ही गोद लिए गए टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरण, विद्यालयों एवं गोद लिए गए गांवों में स्वच्छता अभियान, गुजरात के परंपरागत खेल जैसी सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात ने विकास के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज कर रखा है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को समझना राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना भवन में विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरित की गई तथा उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई।

कुलसचिव केशलाल ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि गुजरात दिवस भारत की सांस्कृतिक विविधता, विकास और एकता का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों से देश की सांस्कृतिक विरासत को समझने और उससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

गोद लिए गए गांव जासोपुर के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय में डॉ. अनुराग मिश्र के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं आदमपुर स्थित कस्तूरबा गाँधी आवासीय स्कूल में डॉ. अन्नू त्यागी एवं डॉ. शशिकांत यादव, डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।

विश्वविद्यालय परिसर में गुजरात के पारंपरिक खेल खो–खो, सतोलिया का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के सफल संचालन में डॉ. सुशील कुमार, प्रभारी तथा डॉ. रजनीश सिंह, सह प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में समन्वयक प्रो. प्रदीप कुमार तथा कार्यक्रम संयोजक प्रो. मनोज मिश्रा नोडल अधिकारी डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर, सह–नोडल अधिकारी डॉ. अन्नू त्यागी एवं डॉ. शशिकांत यादव की महत्वपूर्ण निभाई। इस अवसर पर प्रो. अजय प्रताप सिंह, प्रो. प्रमोद यादव, प्रो. विनोद कुमार, प्रोफेसर गिरधर मिश्र, प्रोफेसर मिथिलेश सिंह, डॉ. रसिकेश, डॉ अमरेंद्र सिंह, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. नितेश जायसवाल, डॉ श्याम कन्हैया, डा. वनिता सिंह, प्रियंका सिंह, डॉ. पुनीत धवन, कर्मचारी सँघ के महामंत्री राधेश्याम सिंह मुन्ना, सुशील प्रजापति, डॉ. इन्द्रेश कुमार समेत कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता रही।

छोटे व बड़े नालों की सफाई 31 मई से पहले पूरी हो – मेयर

अयोध्या।महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा है कि आगामी 31 मई तक नालों की सफाई व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित कर ली जाए।ताकि बरसात के दौरान जल भराव की समस्या पर काबू पाया जा सके। वह नगर आयुक्त श्री जयेंद्र कुमार के साथ नगर निगम के स्वास्थ्य एवं निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे।उन्होंने कहा कि पार्षदों से संपर्क कर एवं स्थानीय नागरिकों से फीडबैक लेकर बरसात के दौरान रास्तों पर जल भराव के संभावित स्थलों को चिन्हित कर लें, जहां आवश्यकता हो, वहां राबिस भर दें ताकि जल भराव के दौरान लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो। उन्होंने जल निकासी के लिए आवश्यकता अनुसार छोटी ड्रेनेज का निर्माण कराने एवं पंप लगाने के लिए स्थलों को चिह्नित कर समय से प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों का बीट निर्धारित कर रोस्टर जारी कर दिया जाए और इसकी नियमित समीक्षा की जाए। नगर आयुक्त ने नाला सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों को 24 घंटे के बाद हटाए गए सिल्ट हटाने का निर्देश दिया। नगर क्षेत्र में 154 बड़े एवं 245 छोटे नालों की सफाई की जानी है। समीक्षा बैठक में महापौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण को गंभीरता से लेने और आम नागरिकों से फीडबैक लेकर खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव, महाप्रबंधक जलकल सौरभ श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएम शुक्ल, सहायक नगर आयुक्त गुरुप्रसाद पांडे आदि मौजूद थे।सेफ्टी टैंक की सफाई करने वाली संस्था के पंजीकरण न कराने पर कार्रवाई होगी।नगर निगम ने समीक्षा बैठक में सेफ्टी टैंक की सफाई करने वाली निजी संस्थाओं को पंजीकरण कराने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। कहा है कि ऐसा न करने पर जांच कराकर अवैध रूप से संचालित संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी। हैदरगंज सेफ्टी टैंक दुर्घटना को देखते हुए नगर निगम का यह कदम आवश्यक माना जा रहा था।हर वार्ड में पांच चरही की स्थापना होगी।पशु पक्षियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने ठोस पहल की है। उसने प्रत्येक वार्ड में पांच–पांच चरही स्थापित करने की योजना बनाई है।नगर आयुक्त ने समीक्षा बैठक के दौरान चरही स्थापित किए जाने वाले स्थान पर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जलकल विभाग को दिए हैं।नगर आयुक्त ने यश पेपर मिल को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया है।बैठक में बताया गया कि मिल से निकलने वाला गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नालों के माध्यम से सरयू नदी में डाला जा रहा है।जनशिकायत को देखते हुए नगर आयुक्त ने अधिकारियों को इसकी जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

'जिलाधिकारी ने जन सुनवाई में सुनी 35 शिकायतें'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' गुरुवार को कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में आज कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को

दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्व और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण हो। जनसुनवाई में प्राप्त कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान किया। जनसुनवाई में उपजिलाधिकारी न्यायिक सदर भूमिका यादव व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारीध्कर्मचारी उपस्थित रहे।

जौनपुर में अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किया प्रदर्शन ,न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के पास प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को उठाया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने षजिला प्रशासन होश में आओष और ष्अधिवक्ता एकता जिंदाबादष जैसे नारे लगाए। यह

प्रदर्शन अधिकारियों के स्थानांतरण पर कार्रवाई न होने और माल अभिलेखागार में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में किया गया। समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह ने बताया कि अधिकारियों के स्थानांतरण पर कार्रवाई न होने और माल अभिलेखागार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ यह प्रदर्शन आवश्यक था। महामंत्री मनोज मिश्रा ने जानकारी दी कि अधिवक्ताओं ने पहले भी एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधिकारियों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया था। उस समय जिलाधिकारी ने एस. आईआर. समाप्त होने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अधिवक्ताओं में असंतोष है। अधिवक्ताओं ने माल अभिलेखागार में व्याप्त भ्रष्टाचार के तत्काल निराकरण की मांग की। इन मुद्दों पर कार्रवाई न होने के कारण समिति ने सभी न्यायालयों से आज के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। आज सभी अधिवक्ता पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे।

सेवानिवृत पुलिस कर्मियों को दी गई विदाई

अयोध्या। सेवानिवृत पुलिस कर्मियों के सम्मान मे एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी व सीओ सदर अरविंद सोनकर ने एसपी ग्रामीण कार्यालय पर विदाई समारोह का आयोजन किया।इस मौके पर उन्होंने सेवानिवृत पुलिस कर्मियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके सुख में जीवन की कामना की।बताते चलें 30 अप्रैल को निरीक्षक रेडियो रेवती रमन सिंह, उपनिरीक्षक शिवपूजन सिंह, महिला उप निरीक्षक मुन्नी देवी, मुख्य आरक्षित मुकेश कुमार मिश्रा तथा राम सिंह सेवानिवृत हुए।इस मौके पर इन दोनों पुलिस अधिकारियों ने सेवानिवृत हुए पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस विभाग में दिये गये योगदान की प्रशंसा करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ, सुखमय जीवन तथा दीर्घायु होने की कामना किया।

अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग कसेगा शिकंजा - डीआईओएस

अयोध्या। डीआईओएस कार्यालय मे सिर्फ एक दर्जन वैध कोचिंग संस्थान ही पंजीकृत है।जबकि जिले के सभी जगहों पर सैकड़ो कोचिंग संस्थान अवैध रूप से संचालित है।इस संबंध में डीआईओएस डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने बताया कि शीघ्र ही अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग शिकंजा कसेगा।बताया कि अवैध रुप से संचालित कोचिंग संस्थानों पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जुर्माना भी लगाया जायेगा।बताया कि अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों पर अंकुश लगाने के लिए डीएम की अध्यक्षता मे समिति गठित की गई है।जिसमे जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी समिति के सचिव हैं।उनके अलावा इस समिति में सीएमओध् अथवा जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ मनोचिकित्सक, जिला कार्यक्रम अधिकारीध, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पुलिस विभाग के उच्चाधिकारीध, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य के दो सामाजिक विधिवेत्ता(जिनमें से एक महिला हो) राष्ट्रीय टास्क फोर्स हेतु नोडल अधि

ाकारी सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं जो अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों पर अंकुश लगायेगे। बताते चलें जिले शहर के विभिन्न मुहल्लों, कालोनियो के अलावा विभिन्न तहसीलों ब्लॉकों पर अवैध रूप से संचालित कोचिंग व शिक्षा संस्थानों द्वारा भोले भाले छात्रों तथा उनके अभिभावकों से शिक्षक के नाम पर भारी भरकम रकम वसूली जा रही है जबकि सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। बताते चलें शहर के नियांवा, रिकाबगंज,साहबगंज, हैदरगंज, वजीरगंज, देवकाली, देवकाली बायपास, देवकाली तिराहा,नाका,सिविल लाइन शाहिद प्रमुख चौराहों पर काफी संख्या मेंअवैध रूप से कोचिंग संस्थान संचालित हैं।वहीं ग्रामीण अंचलों में बीकापुर, तारुन, जाना बाजार हैदरगंज रामपुर बागान मिल्कीपुर गोसाईगंज रुदौली सहित अधिकतर चौराहों व बाजारों में अवैध रूप से कोचिंग संस्थान संचालित है जहां पर शिक्षक के नाम पर दिखावा कर भोले भाले छात्रों व उनके परिजनों से भारी भरकम पैसे वसूल रहे हैं।परंतु इस पर संबंधित विभाग रोक लगाने में असफल दिखाई दे रहा है। अब देखना या है डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य इन अवैध कोचिंग संचालकों पर कब तक रोक लगाते है।

एक्प्रेस-वे विकसित होते भारत की हस्त रेखायें है, ये रेखाये करेगी भारत की उज्जवल भविष्य का जयघोष

आज माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार जी द्वारा जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम निकट मल्लावा कट में आयोजित कार्यक्रम में रुपए 36230 करोड़ की लागत से निर्मित उत्तर प्रदेश के सबसे विराट 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का बटन दबाकर लोकापर्ण किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुचकर सवप्रर्थम गंगा एक्सप्रेस–वे का आवलोकन किया गया और हरि शंकरी उपवन में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम स्थल पर गंगा एक्सप्रेस–वे से संबंधित प्रर्दशनी का आवलोकन किया। इसके उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सर्वप्रथम, मैं भगवान नरसिंह की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है। इसलिए, ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेसवे का ये वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं, और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। मा0 प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में, उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफ लाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले चार–पांच दिनों में, मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है, और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे की बधाई देता हूं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के तेज विकास के लिए हमें तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण करना है। दिसम्बर 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने मैं शाहजहाँपुर आया था। अभी 5 साल से भी कम समय हुआ है, और आप देखिए, देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडॉर एक्सप्रेसवे, ये 5 साल के भीतर–भीतर बनकर तैयार हो गया है, और आज हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। मा0 प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ओर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही, इसके विस्तार की योजना पर काम भी शुरू हो गया है। जल्द ही, गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखघबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर, इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि ये नए बनते एक्सप्रेसवे, विकसित होते भारत की हस्तरेखाएं हैं और ये आधुनिक हस्तरेखाएं, आज भारत के उज्ज्वल भविष्य का जयघोष कर रही हैं। उन्होने कहा कि अब वो दौर चला गया, जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था! एक बार घोषणा हो गई, तो वर्षों तक फाइलें चलतीं थीं! चुनाव के लिए पत्थर लग जाता था, उसके बाद सरकारें आती रहतीं थीं, जाती रहतीं थीं, लेकिन, काम का कुछ अता–पता नहीं लगता था। कभी–कभी तो पुराने फाइलें ढूंढने के लिए बड़े–बड़े अफसरों को दो–दो साल तक मेहनत करनी पड़ती थी। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है, और तय समय में लोकार्पण भी होकर के रहता है। इसलिए ही, आज यूपी के एक्सप्रेसवेज से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है, तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। मा0 प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे केवल एक हाइस्पीड सड़क नहीं है। ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, सम्भल और बदायूँ। मध्य यूपी में शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनके आस पास के दूसरे जिले, गंगा एक्सप्रेसवे, इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक होगी पहुँच, किसानो की आय मे होगी वृद्दि रोजगार के खुलेगे नये अवसर उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों को गंगा जी और उनकी सहायक नदियों की उपजाऊ मिट्टी का वरदान मिला है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर और गर्दन के कैंसर के बढ़ते मामले – एक गंभीर चिंता

आजमगढ़ (आर एल पाण्डेय)।सिर और गर्दन का कैंसर भारत में एक महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य चिंता के रूप में उभर रहे हैं, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ये कैंसर मुंह, गले, स्वरयंत्र और नाक जैसे हिस्सों को प्रभावित करते हैं और अब अधिकतर मामलों में एडवांस्ड स्टेज में सामने आ रहे हैं, जिससे इलाज जटिल हो जाता है और परिणाम भी कम अनुकूल होते हैं। इसका असर खास तौर पर पुरुषों और ग्रामीण व अर्ध–शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसका मुख्य कारण लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें और जागरूकता की कमी है। डॉ. कमलेश वर्मा, डायरेक्टर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ने जोर देकर कहा, ष्बचाव ही सबसे प्रभावी उपाय है। तंबाकू के सभी रूपों से दूर रहना, शराब का सीमित सेवन करना, मुंह की साफ–सफाई बनाए रखना और एचपीवी से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाना इन सभी कदमों से इन कैंसरों के मामलों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सिर और गर्दन के कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू का सेवन है, चाहे वह सिगरेट और बीड़ी के रूप में हो या गुटखा, खैनी और पान मसाला के रूप में हो। बिना धुएं वाला तंबाकू खासतौर से ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि यह सीधे पूरे मुंह को प्रभावित करता है। इसके साथ ही शराब का सेवन जोखिम को और बढ़ा देता है। तंबाकू और शराब का एक साथ उपयोग कैंसर होने की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा, मुंह की ढंग से सफाई न करना, दांतों की धार से होने वाली लगातार चोट और ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) जैसे संक्रमण भी इसके कारणों में शामिल हैं। विशेष रूप से एचपीवी–16 का संबंध गले, टॉन्सिल और जीभ के कैंसर से तेजी से जुड़ता जा रहा है। ऐसे लक्षण जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो बड़ी समस्या खड़ी करते हैं। कैंसरों के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती देर से पहचान होना है, क्योंकि शुरुआती लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर मुंह में दो हफ्ते से ज्यादा समय तक घाव ठीक नहीं हो रहा हो, मुंह के अंदर सफेद या लाल धब्बे दिखाई दें, आवाज में लगातार भारीपन बना रहे, निगलने में दिक्कत हो, बिना वजह खून आए या गर्दन में गांठ महसूस हो तो ये सभी चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज करने से बीमारी चुपचाप गंभीर अवस्था तक पहुंच सकती है। समय पर पहचान होना जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर शुरुआती अवस्था में ही सिर और गर्दन के कैंसर का पता चल जाए, तो इसका इलाज असरदार तरीके से किया जा सकता है और सफलता की संभावना भी काफी अधिक रहती है। खासकर तंबाकू या शराब का सेवन करने वाले लोगों को नियमित रूप से मुंह की जांच करानी चाहिए, जिससे किसी भी असामान्यता का समय रहते पता चल सके। खुद से समय–समय पर जांच करना और किसी भी लगातार बने रहने वाले लक्षण पर डॉक्टर से सलाह लेना भी उतना ही जरूरी है। इलाज कैंसर की अवस्था और उसके स्थान पर निर्भर करता है। इसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी या इनका संयोजन शामिल हो सकता है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की इसमें अहम भूमिका होती है, जिसमें ट्यूमर को आसपास के स्वस्थ टिशू के एक हिस्से के साथ हटाया जाता है, ताकि दोबारा होने की संभावना कम हो सके। हाल के वर्षों में रोबोटिक सर्जरी जैसी नई तकनीकों ने इलाज को और अधिक सटीक बनाया है, जटिलताओं को कम किया है और मरीजों की रिकवरी को बेहतर बनाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर और गर्दन के कैंसर के बढ़ते मामले चिंता का विषय जरूर हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें काफी हद तक रोका जा सकता है। जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच के लिए प्रेरित करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, यह सभी कदम इस बोझ को कम करने में मदद कर सकते हैं। सही समय पर उठाया गया कदम न केवल जीवन बचा सकता है बल्कि प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकता है।

एस.के.डी. एकेडमी के छात्रों ने AIR 4, 7 एवं 8 हासिल कर रचा कीर्तिमान

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एस.के.डी. एकेडमी के छात्रों ने एक बार फिर आई.सी.एस.ई. एवं आई.एस.सी. परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय की गौरवशाली परंपरा को कायम रखा है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी आई.सी.एस.ई. एवं आई.एस.सी.परीक्षाओं का परिणाम 100% रहा। आई.एस.सी. परीक्षा में सुहानी साख्या ने 98.25% अंकों के साथ ।सस प्दकपं 7वां स्थान प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने जेईई

एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई कियाद्य निष्कर्ष त्रिपाठी ने 98% अंकों के साथ ।सस प्दकपं 8वां स्थान प्राप्त किया। आई.सी.एस.ई. परीक्षा में सूर्यांश अवस्थी ने 99.20% अंकों के साथ All India 4 चौथा स्थान प्राप्त किया। दीपांजलि दीक्षित ने 97.4% अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इन होनहार छात्रों को जुलाई माह में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में सम्मानित किया जाएगा। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, अपने माता–पिता, प्रधानाचार्या, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को दिया। छात्रों ने शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज आदि को अपनी सफलता में अत्यंत सहायक बताया। एस.के.डी. ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक श्री मनीष सिंह ने उत्कृष्ट परिणाम के लिए छात्रों एवं शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये छात्र भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर देश की सेवा करेंगे। उन्होंने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी छात्रों को शुभकामनाएं दीं। विद्यालय प्रबंधन कृ अध्यक्ष एस.के.डी. सिंह, निदेशक मनीष सिंह, उप–निदेशिका निशा सिंह, सहायक निदेशिका (शैक्षणिक) कुसुम बत्रा एवं प्रधानाचार्या अंजू सिंह कृ सभी ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सीवर लाइन के नाम पर कार्यदाई संस्था द्वारा शहर के कई गलियों मे खोदे गये गड्ढे की चपेट मे आकर लोग हो रहे चोटिल

अयोध्या। इस समय नगर निगम के अधिकतर मोहल्ले व कॉलोनियों की सड़कों व गलियों मे सीवर लाइन की पाइप डालने के नाम पर गड्ढे तो खोद कर देते हैं लेकिन सीवर लाइन डालने के बाद संबंधित कार्यदायी संस्था ना तो उन गड्ढो को समतल करने की जरूरत समझते हैं और ना ही पहले जैसे सड़क को पुनः निर्माण करने की कवायद करते हैं।जिसके चलते इन मोहल्ले व कॉलोनियों के लोगो को आने–जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर से गुजरने वाले दो पहिया व चार पहिया वाहन चालक भी इन गड्ढे में आकर गिरकर चोटिल भी होते हैं। परंतु इस गंभीर समस्या पर निर्माण करने वाले कार्यदायी संस्थान कोई ध्यान नहीं दे रही।बताते चलें कि शहर के अश्विनी पुरम कॉलोनी, वजीरगंज,हैदरगंज मोहल्ले के अलावा शक्ति नगर कॉलोनी, कसाबबाडा, रिकाबगंज, राठहवेली,कश्मीरी मोहल्ला, साहबगंज, बेनीगंज शाहजहांपुर सहित कई मोहल्ले और कालोनियां है।जहां पर कार्यकारी संस्था द्वारा सिविल लाइन की पाइप बिछाने के नाम पर बड़े–बड़े गड्ढे तो कर देते हैं लेकिन सड.क समतल करने और पहले जैसी सड़क बनाने की कोशिश नहीं करते हैं।इधर से गुजरने वाले छोटे–छोटे बच्चे स्कूली वाहन चालक,दो पहिया वाहन चालक चार पहिया वाहन चालक ई रिक्शा सहित अन्य वाहन इन गड्ढे में गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं।परंतु इस गंभीर समस्या पर किस संबंध कार्यकारी संस्था कोई ध्यान नहीं दे रहा है।इस गंभीर समस्या पर नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि यह बहुत ही गंभीर समस्या है क्योंकि काम करनी से पूर्व संबंधित कार्यकारी संस्थान का यह दायित्व रहता है और उन्हें स्वीकृत करना रहता है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद उन्हें जैसे पाइपलाइन बिछाने से पहले सड़क मिली थी उसी तरीके से पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क को बनवाना पड़ेगा फिलहाल उन्होंने इस संबंध में जांच करवाने की बात कही है।

जाम,पार्किंग व्यवस्था,टूटी सड़के,गंदगी जैसी कई समस्याओं से अयोध्या वासी परेशान

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।जाम, पार्किंग समस्या,पानी की पाइव सीवर लाइन जमीन के अंदर डालने के नाम पर अधूरे निर्माण कार्य जैसी प्रमुख समस्या रामनगरी वासियो के लिए बन चुकी है। जिसके चलते इन गंभीर समस्याओं से यहां के लोगों को तो परेशानी हो ही रही है इसके साथ ही साथ राम मंदिर दर्शन पूजन करने आने वाले दूसरे प्रदेश व देश–विदेश के साथ–साथ दुराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।जिसका प्रमुख कारण इस गंभीर समस्या पर अयोध्या नगर निगम लोक निर्माण विभाग जल निगम यातायात विभाग पुलिस विभाग बिजली विभाग सहित अन्य किस्से संबंधित विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी ध्यान नहीं देते नजर आ रहे हैं। बताते चलें जब से राम मंदिर का निर्माण तथा प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से रामनगरी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आवागमन बनी रहती है। शहर का कोई ही ऐसी गली, कालोनी या मोहल्ला ही शायद बचा हो जहां पर यह समस्या ना हो।कोतवाली नगर क्षेत्र के कसाबबाडा, रिकाबगंज,हैदरगंज, वजीरगंज, पुरानी सब्जी मंडी जिला महिला चिकित्सालय, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, देवकाली बाईपास, नाका बाईपास, रायबरेली बाईपास मार्ग, चौक, फतेहगंज, रिकाबगंज, नियांवा, गुदरी बाजार सहित अन्य प्रमुख मोहल्ले व कॉलोनी है। इसी तरह की गंभीर समस्या अयोध्या धाम पर भी बनी हुई है।अगर दोनों शहरों में जाम की बात करे तो यह जाम सुबह से लेकर देर शाम तक बनी रहती है। सबसे गंभीर स्थिति खासकर नाका, अयोध्या धाम सहित उस समय जाम की उत्पन्न हो जाती है जब राम मंदिर दर्शन के लिए या अन्य किसी कार्यक्रम में किसी विप व्यक्तियों का मूवमेंट रहता है।जिसके चलते स्कूली बच्चे मरीज, बाहर से आने वाले श्रद्धालु व अन्य राहगीर, दो पहिया व चार पहिया वाहन चालक इस जाम में घंटो फंसे रहते है।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी ध्यान नहीं दे रहे है।देखा जाये तो इन चौराहों पर आपको एकाद यातायात के सिपाही मिलेंगे।आधा चौराहा आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर ना तो यातायात सिपाही तैनात मिलेंगे और ना ही यातायात ट्रैफिक लाइट से भीड़ को कंट्रोल करते हुए मिलेगी।इस संबंध मे एसपी यातायात अवधेश प्रताप सिंह ने बताया बात कि विभाग में यातायात पुलिस कर्मी पर्याप्त संख्या में है। जो विभिन्न चौराहों पर तैनात रहते हैं।

कापी,किताब व ड्रेस मामले मे शिक्षकों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर होगी कार्यवाई – बीएसए

अयोध्या। अप्रैल माह से प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल में नया सत्र शुरू हुए 15 दिन से अधिक हो चुका है।बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जहां सभी शिक्षकों को अधिक से अधिक प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल मे बच्चों को पढाने के लिए उनके अभिभावकों से दिशा निर्देश जारी किए।यह बात बीएसए लालचंद ने एक खास मुलाकात में बताई। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी सरकारी तथा प्राइवेट प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों या उनके अभाव को द्वारा साक्षी के साथ जबरन ड्रेस कॉपी किताब जूते मुझे लेने की शिकायत विभाग को मिलती है तो उन स्कूलों के प्रधानाचार्यो तथा शिक्षकों पर कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में पिछले सत्र की अपेक्षा प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल में अधिक से अधिक बच्चों के प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी शिक्षकों को एक टारगेट भी दिया गया है कि वे सभी अपने–अपने क्षेत्र में जाकर बच्चों को तथा उनके माता–पिता को इन स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास यही है की सभी प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई डिजिटल के माध्यम से हो साथ ही साथ सभी प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में कमरे साफ सुथरे हूं प्रकाश की उचित व्यवस्था हो पंख हो शौचालय हूं जिससे अध्यनरत छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो उन्होंने बताया कि उनका प्रयास यही रहेगा कि इस सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में हो शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य अच्छे ढंग से हो सभी स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं हो। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश के लिए अभाव को को प्रोत्साहन हेतु तथा उनका जागरूक करने के लिए रैली आदि निकाली जाती है।

आये दिन विद्युत कटौती से आम जनमानस बेहाल

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। बिजली निगम की ओर से उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति का दावा भले ही किया जा रहा है,लेकिन हकीकत में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं।शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बिजली कब आएगी, कब चली जाएगी, कोई समय तय नहीं है।भीषण गर्मी से लोगों का जीना दुभर हो गया है। रुदौली क्षेत्र मिल्कीपुर क्षेत्र सोहावल क्षेत्र मुमताजनगर क्षेत्र आला अधिकारी को लेकिन जिम्मेदार अभी भी हकीकत पर परदा डाल रहे है।बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।। बीते दो तीन दिनों से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति लगभग पूरी तरह बंद रही। शुक्रवार सुबह को भी यही हाल था। सोहावल तहसील रौनाही आर एल ग्रामीण नगर पंचायत सभी सप्लाई बंद 30 घंटे मे तीन घंटे न हो सकी सप्लाई।अवर अभियंता सोहावल से संपर्क हो नहीं सकता क्योंकि उनका सीयूजी नंबर कभी उठता ही नही।वही विधायक प्रतिनिधि भी हुए जवाब हीन सोहावल क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हुई पूरी तरह फेल इस मुद्दे पर ना तो सत्ता पक्ष संवेदनशील है और ना ही विपक्ष भाजपा सरकार बिजली कटौती में सबसे ज्यादा आगे निकल गई है दिन से लगातार बिजली कटौती की गई जिससे शुक्रवार को शाम को 30 मिनट के लिए सभी जनमानस को बिजली मिली उसके बाद रोस्टिंग टाइम से 8 .15 रोस्टिंग टाइम 9.15 मिनट का था उसके 30 मिनट सप्लाई मिली लेकिन रोस्टिंग का एक बहाना बना बता कर जनता को गुमराह लगातार किया जा रहा है 9.45 से फिर रोस्टिंग किया गया था 10.45 एक घंटे में बिजली मिली फिर उसके बाद फिर से रोस्टिंग टाइम टेबल सेट कर दिया गया है पूरे दिन रोस्टिंग पूरी रात रोस्टिंग टाइम है उसके बाद रोस्टिंग टाइम जनता का बुरा हाल है गर्मी बेमिसाल है न तो सत्तापक्ष के जनप्रतिनिधि भी बिजली कटौती पर एक शब्द तक आवाज नही उठाया ओर न ही विपक्ष इस दौरान किसान को अपनी को गन्ने की फसल पिपरमिंट टमाटर की खेती लौकी तरोई फसल को सीचने के लिए परेशान हो रहा है परंतु समय से किसान का बिल भुगतान न हो तो बिजली विभाग के अधिकारी ट्यूबल का कनेक्शन काटने के लिए सो कर उठ जाते हैं उसी समय जनमानस अगर बिल भुगतान नही दिया तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है इस दौरान अगर किसी फीडर फोन किया जाए तो किसी भी फीडर पर फोन नही लगता है

आग लगने की सूचना घबराहट मे न दे लोग - सीएफओ

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।आग लगने की सूचना अग्निशमन नियंत्रण कक्ष को बिना घबराहट के दे।इस संबंध में बात करते हुए सीएफओ एमपी सिंह ने जिले वासियों से अपील किया कि आग लगने की सूचना देने वाले व्यक्ति यह जरूर बताएं कि आग कहां पर लगी है वहां पर छोटी दमकल जा सकती है या बड़ी दमकल।इन वाहनों के जाने के लिए घटनास्थल तक सड़क है या नहीं।उसी हिसाब से मुख्यालय से छोटे बड़े दमकल घटना स्थल तक भेजी जाए उन्होंने बताया कि प्राय यह देखने में आता है की लोग घबराहट में आग लगने की सूचना तो मुख्यालय को दे देते हैं लेकिन सही–सही जानकारी नहीं देते कि आज कहां लगी है वहां पर कौन सी दमकल जा सकती है।जहां पर आग लगी है वह गली के अंदर है यह मुख्य मार्ग पर उन्होंने लोगों से अपील किया कि जब जिला मुख्यालय को सही सूचना मिलेगी तो इस सूचना के आधार पर यहां से अग्निशमन विभाग के वहां जाकर आग पर काबू पा सकेंगे।उन्होंने बताया इस समय अग्निशमन जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है।शहर के अलावा जिले के विभिन्न तहसीलों में स्थित स्कूलों कॉलेज बाजारों सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर पंपलेट पोस्टर बैनर तथा रैलियों के माध्यम से वहां के लोगों को आग से बचाव हेतु जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस समय अप्रैल माह चल रहा है अप्रैल में जून 3 माह में अधिक आग लगने की घटनाएं घटित होती हैं इसलिए आज से बचाव है तू जानकारी रखनी चाहिए साथ ही साथ सावधानी भी बरतनी चाहिए क्योंकि एक छोटी सी हल्की सी लापरवाही बहुत बड़े नानी का कारण बन सकती है। उन्होंने शहर वासियों तथा ग्राम वासियों से अपील किया है कि वे सभी रात में सोते समय सिलेंडर का उपयोग न होने पर रेगुलेटर से गैस को बंद कर दे। वही अगर कोई शादी विवाह या अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में अपने घरों से जा रहा है तो एमसी और कोशिश या रहे मैन स्विच से लाइट को बंद कर दे जिससे कि शार्ट सर्किट से अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने वही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तथा किसानों से भी अपील किया है कि इस समय गर्मी चरम पर है और खासकर गेहूं की फसलों में आग लगने की घटनाएं अधिक हो रही है इसलिए कोसी से ही रहे की किसान भाई तथा अन्य लोग खेतों के आसपास धूमपान ना करें क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे गेहूं के खेत को जला सकती है।वही ग्रामीण अंचलों की महिलाओं से भी अपील किया है की चूल्हे पर खाना बनाने के बाद उसके रख को पानी से पूरी तरह से बुझा दें और तीन–चार घंटे बाद ही बाहर फेके और कोशिश यह रहे जहां पर ठेके वहां पर कूढे ना इकट्ठे हो।

सरकारी भूमि पर गांव के रसूखदार व भूमाफियाओं की नजर, तहसील प्रशासन की नहीं पहुंच रही नजर

अयोध्या। ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराने का उच्चन्यायालय व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पारित आदेश का पालन कराने में राजस्व कर्मियों के पसीने छूट रहे है।अवैध कब्जा मुक्त कराना तो दूर की बात रही यहां गांव के रसूखदार व भूमाफियाओं की बल्ले बल्ले है। चंद्र सिक्कों के खनक के आगे राजस्व महकमा पूरी तरह से रसूखदार व भूमाफियाओं के सामने नमस्तक नजर आ रहा है।मामला तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भेलसर ग्राम पंचायत का है।जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि गाटा संख्या 1185 राजस्व अभिलेख में तालाब दर्ज है। इसी क्रम में गाटा संख्या 1180 राजस्व अभिलेख में खेल का मैदान, गाटा संख्या 1085 राजस्व अभिलेख में बंजर, गाटा संख्या 1084 वर्ग क्षेत्र 2 की आबादी गाटा संख्या 1292 राजस्व अभिलेख में स्वयं तहसील के नाम दर्ज है। गाटा संख्या 1290 वर्ग क्षेत्र 2 की आबादी दर्ज है।गाटा संख्या 1447 राजस्व अभिलेख में बंजर दर्ज है गाटा संख्या 1448 राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज है गाटा संख्या 1449 राजस्व अभिलेख में बंजर दर्ज है।गाटा संख्या 1428 राजस्व अभिलेख में खाद्य गड्ढा, गाटा संख्या 1427 राजस्व अभिलेख खाल निकालने के नाम दर्ज है।गाटा संख्या 1443 राजस्व अभिलेख में सूअर बाड़ा दर्ज है। गाटा संख्या 1439 राजस्व अभिलेख में तालाब दर्ज है गाटा संख्या 1034 राजस्व अभिलेख में तालाब दर्ज है।गाटा संख्या 1021 राजस्व अभिलेख में तालाब दर्ज है गाटा संख्या 1248 राजस्व अभिलेख में नाली दर्ज है जिस पर भूमाफियाओं द्वारा प्लाटिंग कर दिया गया है।इसके अतिरिक्त गाटा संख्या 1205 नवीन परती, गाटा संख्या 1262 राजस्व अभिलेख में बंजर गाटा संख्या 1256 राजस्व अभिलेख में चकमार्ग व 1158 मिन राजस्व अभिलेख में तालाब दर्ज है।ग्रामीणों की माने तो लेखपाल की मिलीभगत से गांव के रसूखदार व भूमाफियाओं द्वारा कुछ जमीन पर प्लाटिंग करके बिक्री की जा रही है तो कुछ जमीन को अवैध रूप कब्जा कर लोग अपना अपना आशियाना खड़ा कर रहे है।ऐसा नहीं है कि मामला तहसील प्रशासन के जानकारी में नहीं सबकुछ जानते हुए तहसील प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।चर्चा है कि अधिकांश अवैध कब्जा धारक ग्राम प्रधान के करीबी या रिश्तेदार है।मामले को लेकर एसडीएम ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी।

अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था के चलते रेल यात्री रहते हैं परेशान

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या आने वाले रेल यात्रियों व श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन उनके सुविधा के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं है।जिसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला।यहां पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेल विभाग द्वारा कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया है।जिसके चलते इधर से आने जाने वाले रेल यात्रियों का आक्रोश यहां के रेल अधिकारियों, कर्मियों के साथ–साथ रेल विभाग के उच्च अधिकारियों पर दिखाई देता है।नाम न छापने के शर्त पर इधर से गुजरने वाले रेल यात्रियों ने बताया कि इस स्टेशन से कई ट्रेन में बनकर भी चलती है जिसके चलते पहले से पहुंचे रेल यात्रियों को प्रतीक्षालय में बैठने के लिए जगह तक नहीं उपलब्ध रहती।देखा जाय तो यहां पर दो प्रतीक्षालय पुराने जमाने के बने हुए हैं।जिसमे एक महिला तथा एक पुरुष प्रतीक्षालय है।कम जगह होने के चलते मजबूरी में महिलाओं पुरुषों को एक में ही बैठना पड़ता है।रेल यात्रियों की माने तो यहां पर लगे एसी तक भी समय–समय पर नहीं चलती हैं।जिसके चलते खास कर बंदे भारत सहित अन्य ट्रेनों से आने जाने वाले रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहां पर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी राम भरोसे है।क्योंकि यहां पर लगे अधिकतर सीसीटीवी कैमरे भी खराब है और मुख्य द्वार से अंदर आने वाले रेल यात्रियों के सामान भी नहीं चेक हो पाए क्योंकि इन सामानों को चेक करने वाली मशीन भी काफी दिनों से खराब पड़ी हुई है।वही रेल यात्रियों की माने तो इस स्टेशन पर सफाई काम गंदगी का साम्राज्य ज्यादा है जिसके चलते संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है।देखा जाए जबकि अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन अति महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है यहां से दर्जनों गाड़ियां बनकर चलती हैं लेकिन रेल यात्रियों के सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है।

मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला एसओ आशा शुक्ला व महिला उप निरीक्षक चेतना पाण्डेय द्वारा लगातार किया जा रहा जागरूक

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। गुरुवार को एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर तथा मिशन शक्ति फेज 5 के नोडल प्रभारी व एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के निर्देश पर सीओ सिटी श्रीयेश त्रिपाठी की देखरेख मे महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने महिला उप निरीक्षक चेतना पांडे ने महिला कांस्टेबल शशिलता, महिला होमगार्ड शोभावती व महिला पुलिसकर्मियों के साथ जिला महिला चिकित्सालय,जिला पुरुष चिकित्सालय, रिकाबगंज, बल्लाहाता,चौक रोडवेज, गुरुगोविंद सिंह चौक, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन सहित अन्य प्रमुख चौराहा तथा मार्गों पर महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया।इस मौके पर उन्होंने मिशन शक्ति अभियान फेज फाइव के तहत सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी देते हुए बताया कि जिससे कभी भी संकट के समय आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं।इस मौके पर उनके साथ मौजूद रही महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौर ने बालिकाओं से कहीं।उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए जहां एक तरफ उनके विकास को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण सुकन्या समृद्धि योजना सहित एक से बढ़कर एक कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चल रही हैं।इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद बालिकाओं को पंपलेट व बैनर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना का अंदेशा हो तो बिना झिझक अपने नजदीकी पुलिस कर्मियों, महिला थाना तथा अपने परिजनों को फोन पर बताये।इस मौके पर उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

'स्कूली वाहनो के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रपत्र तीन दिन में बनवायें–ए0आर0टी0ओ0'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासनध्प्रवर्तन ने समस्त स्कूली वाहन स्वामियों, विद्यालय प्रबन्धकों प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि जिन स्कूली वाहनों के प्रपत्र परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण इत्यादि समाप्त हो गया है तीन दिन के अन्दर कराना सुनिश्चित करें। प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान यदि उक्त वाहन प्रपत्र परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण इत्यादि वैधता समाप्त संचालित पायी जायेगी, तो उसके विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।

अयोध्या के कांग्रेस नेताओं ने दी अपने नेता को श्रद्धांजलि

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, छात्र राजनीति से ही कांग्रेस पार्टी में सक्रिय शेषनाथ दुबे के निधन पर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने किया तथा संचालन जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने किया।कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉ निर्मल खत्री ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शेष नाथ दुबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही बताया और कहा हमें ऐसे साथी के खोने का गम हमेशा रहेगा कांग्रेस पार्टी में इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है।पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कांग्रेस नेता शेष नाथ दुबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा हमें दुख है हमने एक पार्टी का वफादार साथी खो दिया।महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा श्री शेष नाथ दुबे का निधन कांग्रेस पार्टी के लिए आघात है।कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस नेता शेषनाथ दुबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही बताया।जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने कहा शेष नाथ दुबे का आकस्मिक निधन का समाचार स्तब्ध करने वाला रहा, उनका निधन अत्यंत दुखदाई है , उनके निधन के पश्चात जो स्थान रिक्त हुआ उसकी भरपाई नहीं की जा सकती।शोक सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा की शांत के लिए प्रार्थना की गई।शोक सभा मे उपस्थित प्रमुख लोगों में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ,पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा,अनिल तिवारी ,अश्वनी सिंह मधुर,धर्मेंद्र सिंह पास्टर, बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री गिरीश तिवारी, महेश वर्मा, उमेश उपाध्याय,मंसाराम यादव , सुरेंद्र सिंह सैनिक, प्रवीण श्रीवास्तव, नाजिश फातिमा,दानिश जिया,फ्लावर नकवी, बसंत मिश्रा ,भगवान बहादुर शुक्लआदि प्रमुख लोग रहे।

'दहेज की मांग या इससे जुड़ी प्रताड़ना का मामला होने पर होगी कड़ी कार्यवाही:–संजय कुमार निगम'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने सूचित किया है, कि समाज में व्याप्त दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। इस कानून के अंतर्गत दहेज लेना और दहेज देना, दोनों ही दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति (सम्पत्ति के कागजात आदि) की मांग करना अपराध है। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है, देता है या दहेज लेने देने में मदद करता है, तो उसे कम से कम 5 वर्ष के कारावास और 15,000 रूपये या दहेज के मूल्य के बराबर (जो भी अधिक हो) जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने बेटे, बेटी या रिश्तेदार के विवाह के बदले समाचार पत्र या अन्य माध्यमों से संपति या व्यापार में हिस्सेदारी का प्रस्ताव (विज्ञापन) देता है, तो उसे 6 महीने से 5 वर्ष तक की जेल हो सकती है। विवाह के समय दिए जाने वाले स्वेच्छापूर्वक उपहारों (जो दहेज की श्रेणी में नहीं आते) की एक हस्ताक्षरित सूची बनाना अनिवार्य है। जिला प्रशासन सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं और अभिभावकों से अपील करता है कि वे दहेज मुक्त विवाह का संकल्प लें। यदि आपके संज्ञान में दहेज की मांग या इससे जुड़ी प्रताड़ना का कोई मामला आता है, तो तुरन्त संबंधित थाना या जिला प्रोबेशन कार्यालय में रिर्पोट करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। दहेज एक सामाजिक कलंक है। आइए, मिलकर एक सभ्य और सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।

दुकानदार व श्रद्धालु में मारपीट का वीडियो वायरल,जांच में जुटी पुलिस

अयोध्या। अयोध्या धाम में आए दिन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटना आम हो गई है जिसके चलते अयोध्या धाम की छवि भी कुछ अराजक तत्वों व अतिक्रमणकारियों के कारण धूमिल हो रही है। परंतु श्रद्धालुओं से मारपीट करने वाले लोगों पर पुलिस अंकुश नहीं लग पा रही है जिसके चलते श्रद्धालुओं के अलावा अन्य लोगों में कोतवाली अयोध्या पुलिस के साथ–साथ थाना रामजन्म भूमि पुलिस के कार्य शैली पर उंगलियां उठ रहे हैं और उनके प्रति आक्रोश व्याप्त है। बताते चलें रामपथ छोटी देवकाली के पास श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला फिर हुआ। जबकि अभी कुछ दिन पहले श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला राम जन्मभूमि मंदिर के पास भी हुआ था।प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रामपथ छोटी देवाकाली के पास स्थित मौर्या मिष्ठान के सामने मामूली कहासुनी के बाद एक व्यक्ति श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने लगा।देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर लात–घूंसे चले।जिसका वीडियो सामने आया है।बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाला व्यक्ति भाजपा कार्यकर्ता है।हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत मामूली बात को लेकर हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि व्यक्ति और श्रद्धालुओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई।मौके पर अफरा–तफरी का माहौल बन गया।विवाद बढ़ता देख स्थानीय लोग मौके पर आकर मामले को शांत कराया। इस संबंध में जब प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या पंकज सिंह से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो काल जाने के बाद भी फोन रिसीव नहीं हुआ।सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है मारपीट की घटना मामूली बातों को लेकर हुई थी लेकिन पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ कार्यवाही करेगी।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।